

TO BE PUBLISHED IN PART-II (a) OF THE LEGISLATIVE
SUPPLEMENT OF THE U.P. GAZETTE EXTRAORDINARY, DATED
AUGUST 08 , 2012 POSITIVELY

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG- 1
NO. 598(2) /79-V-1-12-2(ka) 5/2012
Lucknow: Dated: August 08, 2012

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Sthaniya Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhyadesh, 2012 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2012) promulgated by the Governor:-

(Here print the annexed)

By order,

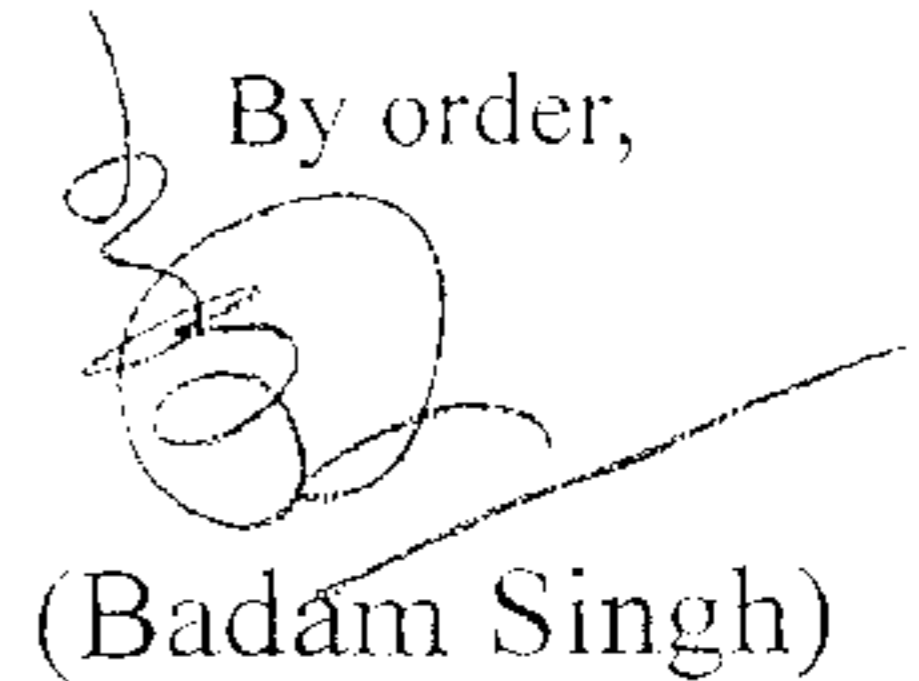
Zaki Ullah Khan,
Pramukh Sachiv.

NO. 598(3)/79-V-1- 12-2(Ka) 5/ 2012 of date

Copy forwarded for information and necessary action to,-

1. Mukhya Mantri, Uttar Pradesh.
2. Mukhya Sachiv, Uttar Pradesh Shasan.
3. Pramukh Sachiv, Nagar Vikash Anubhag-1, Uttar Pradesh Shasan.
4. Pramukh Sachiv, Vidhan Sabha, Uttar Pradesh.
5. Pramukh Sachiv, Vidhan Parishad, Uttar Pradesh.
6. Soochna Nideshak, Uttar Pradesh.
7. Pramukh Sachiv, Rajyapal , Uttar Pradesh.
8. Vidhi Paramarshi Pustakalaya, Uttar Pradesh Sachivalaya.
9. Sansadiya Karya Anubhag-1
10. Bhasha Anubhag-5, Uttar Pradesh Sachivalaya.
11. Vidhayi Anubhag-2, Uttar Pradesh Sachivalaya

By order,



(Badam Singh)

Vishesh Sachiv Evam
Upper Vidhi Paramarshi.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS
(AMENDMENT) ORDINANCE, 2012

(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2012)

(Promulgated by the Governor in the Sixty third Year of the Republic
of India)

AN
ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the
Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor is
satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take
immediate action;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1)
Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to
promulgate the following Ordinance:-

CHAPTER-1

Preliminary

- Short title and Commencement** 1- (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh
Urban Local Self Government Laws
(Amendment) Ordinance, 2012
(2) It shall be deemed to have come into force on
September 15, 2006.

CHAPTER-2

**Amendment of the Uttar Pradesh Municipalities
Act, 1916**

- Amendment of Section 9-A of U.P. Act No. 2 of 1916** 2- In section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act,
1916, in sub-section (5), in clause(1) after sub-
clause(f) the following Explanation shall be inserted
and be deemed to have been inserted on September 15,
2006, namely :-

“Explanation I : It is hereby clarified that the words
“previous election” and “subsequent election” as
occurring in sub-clause (f) of this clause and
elsewhere in the Act shall not include and shall be

deemed to have never included the elections held in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2006 (Uttar Pradesh Ordinance no. 3 of 2006) and this Act as amended by the said Ordinance.

Explanation II- Notwithstanding the repeal of the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 3 of 2006) and its substitution by the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 25 of 2006) or the judgement, order or decree of any Court, Tribunal or Authority it is hereby declared that the elections held in accordance with the provisions of the said Ordinance and this Act as amended by the said Ordinance shall not be deemed to be the "previous election" as contemplated under this section and the next elections to be held under this section accordingly shall not be deemed to be subsequent election."

CHAPTER-3

Amendment of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959

Amendment of Section 7 of U.P. Act No. 2 of 1959

3- In section 7 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, in sub-section(5), in clause(1), after sub-clause (f) the following Explanations shall be inserted and be deemed to have been inserted on September 15, 2006, namely :-

“Explanation I : It is hereby clarified that the words “previous election” and “subsequent election” as occurring in sub-clause (f) of this clause and elsewhere in this Act shall not include and shall be deemed to have never included the elections held in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance No. 4 of 2006) and this Act as amended by the said Ordinance.

Explanation II- Notwithstanding the repeal of the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2006 (U.P. Ordinance no. 4

of 2006) and its substitution by the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 25 of 2006) or the judgement, order or decree of any Court, Tribunal or Authority it is hereby declared that the elections held in accordance with the provisions of the said Ordinance and this Act as amended by the said Ordinance shall not be deemed to be the "previous election" as contemplated under this section and the next elections to be held under this section, shall not be deemed to be subsequent election."

B.L. Joshi
Governor
Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या:.....5.....सन् 2012)

(भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल-निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

- | | | |
|---------------------------|--------|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1--(1) | यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2012 कहा जायेगा। |
| | (2) | यह 15 सितम्बर, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा। |

अध्याय-2

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

- | | | |
|---|----|---|
| उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1916 की धारा 9-क का संशोधन | 2- | उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9-क में, उपधारा (5) में, खण्ड(1) में उपखण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा और उसे 15 सितम्बर, 2006 को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :-
“ स्पष्टीकरण-एक :- एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड (च) में और अधिनियम में अन्यत्र आने वाले |
|---|----|---|

शब्द "परवर्ती निर्वाचन" और "पश्चातवर्ती निर्वाचन" में उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 2006) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुये निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किये गये समझे जायेंगे।"

"स्पष्टीकरण-दो :- उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3, सन् 2006) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2006) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात "परवर्ती निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे और इस धारा के अधीन होने वाले आगामी निर्वाचन तदनुसार "पश्चातवर्ती निर्वाचन" नहीं समझे जायेंगे।"

अध्याय-तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

3- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 7 में, उपधारा (5) में, खण्ड (1) में उपखण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा और उसे 15 सितम्बर, 2006 को बढ़ाया हुआ समझा जायेगा, अर्थात् :-

" स्पष्टीकरण-एक :- एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खण्ड के उपखण्ड(च) में और इस अधिनियम में अन्यत्र आने वाले शब्द "परवर्ती निर्वाचन" और "पश्चातवर्ती निर्वाचन" में उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश

अध्यादेश संख्या 4, सन् 2006) और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुये निर्वाचन सम्मिलित नहीं होंगे और वे कभी भी सम्मिलित नहीं किये गये समझे जायेंगे।”

“स्पष्टीकरण-दो :- उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4, सन् 2006) के निरसन और उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, सन् 2006) द्वारा उसके प्रतिस्थापन या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के निर्णय, आदेश या डिक्री के होते हुए भी, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त अध्यादेश और उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हुए निर्वाचन इस धारा के अधीन यथा अनुध्यात “परवर्ती निर्वाचन” नहीं समझे जायेंगे और इस धारा के अधीन होने वाले आगामी निर्वाचन “पश्चातवर्ती निर्वाचन” नहीं समझे जायेंगे।”

बी०एल०जोशी

राज्यपाल

उत्तर प्रदेश।